भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1415

दिनांक 02.12.2014/ 11 अग्रहायण, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

आपदा – प्रबंधन केन्द्र

1415. श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आतंदराव अडसुल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुस ने मॉस्को स्थित आपदा-प्रबंधन केन्द्र की तर्ज पर भारत में भी आपदा प्रबंधन केन्द्रों की स्थापना हेतु तकनीकी मदद की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का एक संकट प्रबंधन केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क)एवं(ख): भारत तथा रुस ने एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके द्वारा कोई भी देश आपातकाल के मामले में विशेषज्ञ दलों, उपकरणों, आपूर्ति और सहायता सामग्री के आदान-प्रदान के माध्यम से दूसरे देश से सहायता की मांग कर सकता है। इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाने के दृष्टिकोण से, "राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डाटाबेस" नामक परियोजना के चरण-। को आरंभ कर दिया है। एक पायलट परियोजना शुरु करने का भी निर्णय लिया गया था, जो 4 राज्यों के 10 जिलों में शुरु की जाएगी। पायलट परियोजना में रसियन इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट कमांड सेंटर के साथ समानताएं हैं जैसे जीआरएस आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन; दोहरा विडियो, ऑडियो तथा संचार क्षमताएं तथा यह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जैसी तकनीकी पूर्वानुमान एजेंसियों से इनपुट प्राप्त कर सकती है। तथापि, यह वर्तमान संगठनों के विलय अथवा नए मंत्रालय के निर्माण के बगैर हमारी संघीय नीतिपरक आवश्यकताओं के अनुकूल होने के संबंध में आपदा प्रबंधन के मामले में राज्य सरकार की भूमिका की दृष्टि से रुस से मॉडल से भिन्न है।

(ग)एवं(घ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 25 सितम्बर, 2014 को 18 माह की अवधि के भीतर क्रियान्वित किए जाने के लिए 19.64 करोड़ रु. के परिव्यय से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कमांड सेंटर के गठन के लिए एक पायलट स्कीम को मंजूरी दी गई थी। इस स्कीम में राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर इमरजेंसी आपरेशन कंट्रोल के लिए जीआईएस आधारित आडियो, वीडियो तथा डाटा-कम्यूनिकेशन का प्रावधान है। पायलट परियोजना से प्राप्त जानकारी नेशनल डाटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट के चरण-।। के आगामी विस्तार में सहायता प्रदान करेगी।